पटना उच्च न्यायालय के

विशेष पीठ में

दीवानी संदर्भ सं.- 02/1952

निर्णय तिथिः 30.11.1953

अपीलकर्तागणः **श्री गौरी शंकर प्रसाद के मामले में**

लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879-धारा 14 - कारिंदा समझकर निर्देश लेने वाले वकील के खिलाफ कार्यवाही शुरू, पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं। पक्ष द्वारा वकील के पक्ष में कोई वकालतनामा निष्पादित नहीं किया गया। (कंडिका - 1)

याचिकाकर्ता ने राजेंद्र प्रसाद से वकालतनामा प्राप्त किया, जो मानते थे कि वह मुवक्किल का करिंडा है, उसे यह नहीं कहना चाहिए था कि उसने मुवक्किल से प्राप्त किया-वकील न तो मुवक्किल और न ही उसके मान्यता प्राप्त एजेंट से निर्देश प्राप्त करने का दोषी है-वकील अनुचित आचरण करने के दोषी है-एल. डी. की सिफारिश। वकील को तीन महीने के लिए निलंबित करना अधीनस्थ न्यायाधीश ने स्वीकार किया-एल. डी. जिला न्यायाधीश आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट भेजने से पहले अपनी राय दर्ज करेंगे।(कंडिका-3,4,5)

पटना उच्च न्यायालय के

विशेष पीठ में

दीवानी संदर्भ सं.- 02/1952

निर्णय तिथिः 30.11.1953

अपीलकर्तागणः **श्री गौरी शंकर प्रसाद के मामले में**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

दास, जुगल किशोर नारायण और जमुआर, न्यायमूर्तिगण

अधिवक्तागणः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः सरकारी अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/प्रतिवादी के लिएः बी.एन. मित्तर, कृष्ण प्रकाश सिन्हा और रमाकांत वर्मा, अधिवक्ता

आदेश

1. यह छपरा के पेशेवर वकील श्री गौरी शंकर प्रसाद के संबंध में कानूनी व्यवसायी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक प्रतिवेदन है।

तथ्य विवादित नहीं हैं। श्री गौरी शंकर प्रसाद मार्च, 1947 में जिला अधिवक्ता संघ में शामिल हुए। 19-12-1949 को, उन्होंने कुछ दस्तावेजों और वकालतनामे को वापस करने के लिए एक आवेदन दायर किया। वकालतनामा पर, इस आशय का समर्थन किया गया था कि यह स्वयं एक मुवक्किल, पारसनाथ तिवारी से प्राप्त हुआ था। विद्वान वकील द्वारा दायर वकालतनामे के बल पर, दस्तावेज़ उन्हें वापस कर दिए गए।

यह बाद में एक सत्र वाद में सामने आया जहां वकील ने सबूत दिया कि वह पारसनाथ तिवारी को बिल्कुल नहीं जानता था और उसे उनसे कोई वकालतनामा नहीं मिला था। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता ने राजेंद्र प्रसाद से वकालतनामा प्राप्त किया था, जो अधिवक्ता ने कहा कि वह पारसनाथ तिवारी का 'प्रतिनिधि' था। यह साबित हो गया कि पारसनाथ तिवारी ने वकील के पक्ष में कोई वकालतनामा नहीं जारी किया था; राजेंद्र प्रसाद उनके 'प्रतिनिधि' नहीं थे और जो दस्तावेज विद्वान वकील ने वापस ले लिए थे, वे पारसनाथ तिवारी को नहीं सौंपे गए थे।

इन परिस्थितियों में, वादी के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति से निर्देश लेने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी जो न तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्थ के भीतर किसी पक्ष का मान्यता प्राप्त एजेंट था और न ही निर्देश देने के लिए पक्ष द्वारा अधिकृत एक नौकर, रिश्तेदार या दोस्त; और अपने पेशेवर कर्तव्य के निर्वहन में घोर अनुचित आचरण का भी दोषी था।

2. जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, तथ्य विवाद में नहीं हैं। यदि विद्वान वकील ने राजेंद्र प्रसाद से वकालतनामा प्राप्त किया, जिन्हें वह पारसनाथ तिवारी का 'करिंदा' मानते थे, तो उन्हें वकालतनामा में यह नहीं कहना चाहिए था कि उन्होंने इसे स्वयं पारस नाथ तिवारी से प्राप्त किया था। छपरा के विद्वान द्वितीय अधीनस्थ न्यायाधीश, जिन्होंने वादी के खिलाफ जांच की थी, ने पाया है कि वादी अपने खिलाफ लगाए गए दोनों आरोपों के लिए दोषी था; अर्थात् वह एक ऐसे व्यक्ति से निर्देश प्राप्त करने का दोषी था जो न तो एक पक्ष था और न ही किसी पक्ष का मान्यता प्राप्त एजेंट था और न ही एक नौकर, दोस्त या रिश्तेदार जो पक्ष की ओर से निर्देश देने के लिए विधिवत अधिकृत था; उसने यह भी पाया है कि वादी वकालतनामा पर समर्थन करने में घोर अनुचित आचरण का दोषी था कि उसने इसे पारसनाथ तिवारी से प्राप्त किया था, हालांकि वह उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था।

3. हम संतुष्ट हैं कि वकील के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। प्लीडर की ओर से पेश श्री बी. एन. मित्तर ने सुझाव दिया है कि हमें उनके मुवक्किल के साथ नरमी से व्यवहार

करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि प्लीडर 1947 में ईयर में शामिल हुआ और दुखद घटना, जिसमें से प्लीडर के खिलाफ आरोप सामने आए हैं, लगभग दो साल के भीतर, अर्थात् 39-12-1919 पर हुई। उन्होंने आगे कहा है कि इन कठिन दिनों में वकील से नरमी से निपटा जाना चाहिए और कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि वकील, जो एक बहुत ही कनिष्ठ अधिवक्ता है, को केवल तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है। इस मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम नहीं सोचते कि वकील को केवल चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। हम तदनुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश की सिफारिश को स्वीकार करेंगे और इस तारीख से केवल तीन महीने की अवधि के लिए वादी को निलंबित करेंगे। बार में कहा गया है कि प्लीडर आज अदालत में मौजूद है, और हमने उसे आदेश की सूचना दी है।

5. इस मामले के साथ भाग लेने से पहले, हमें यह इंगित करना चाहिए कि विद्वान जिला न्यायाधीश, जिन्होंने द्वितीय अधीनस्थ न्यायाधीश की रिपोर्ट भेजी थी, ने धारा 14 कानूनी व्यवसायी अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया था। उस सेक्शन में यह अपेक्षा की गई है कि जब जिला न्यायाधीश द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है, तो उसे इस न्यायालय को भेजने से पहले अपनी राय दर्ज करनी चाहिए।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।